

न्यायालय राजस्व मंडल, मध्य प्रदेश ग्वालियर
समक्ष
एम० के० सिंह
सदस्य

निगरानी क्रमांक ४७-दो/१९९० - विरुद्ध आदेश दिनांक २०.४.
१९९० पारित द्वारा अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना - प्रकरण
क्रमांक ९५/१९८५-८६

१- श्रीमती जावित्री (मृतक) पुत्री महाराज सिंह
बेओलाद फोट वारिस केता

२- रामवीर पुत्र सभाराम, निवासी
अरदोनी तहसील व जिला मुरैना
विरुद्ध

---आवेदकगण

१-सालिगराम पुत्र शंकर सिंह
ग्राम अरदोनी तहसील मुरैना
२-नारायण (मृतक) पुत्र गेंदालाल
वारिस

१. जनकसिंह
२. बहादुर सिंह
३. बासुदेव सिंह
४. मानसिंह चारों पुत्र नारायण
५. सुश्री मुन्नीवाई पुत्री नारायण

३- हरीसिंह पुत्र गेंदालाल
दोनों निवासी ग्राम बमरौली
तहसील व जिला मुरैना

---अनावेदकगण

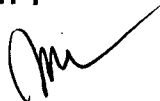
(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस.के.अवस्थी)
(अनावेदक -१,३ के अभिभाषक श्री मुकेश बेलापुरकर)
(अनावेदक-२ के वारिसान के अभिभाषक श्री सी.एम.गुप्ता)

आ दे श
(आज दिनांक २०-१०-२०१५ को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण
क्रमांक ९५/१९८५-८६ अपील में पारित आदेश दिनांक २०.०४.
१९९० के विरुद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा
५० के अंतर्गत प्रस्तुत है।

2/ प्रकरण का सारौंश यह है कि ग्राम अरदौनी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 736 रकबा एक वीघा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) मृतक दाताराम एवं गेंदालाल के नाम पर भूमिस्वामी स्वत्व पर थी, जिनकी मृत्यु उपरांत आवेदक क्रमांक 1 ने अपने जीवनकाल में आवेदक क्रमांक-2 को विक्रय कर दी। इसी पर अधिपति कृषक घोषित करने हेतु अनावेदक सालिगराम, नारायण एवं हरीसिंह ने तहसील न्यायालय मुरैना में दावा दायर किया जो तहसील न्यायालय नायब तहसीलदार मुरैना में प्रकरण क्रमांक 21/83-84X110,190 पर दर्ज होकर आवेदकगण को आदेश दिनांक 26-9-84 से अधिपति कृषक घोषित किया गया। इसके बाद अनावेदक ने म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 190/110 के अंतर्गत दावा दायर किया जो प्रकरण क्रमांक 18/83-84 अ-46 पर पंजीबद्ध हुआ तथा पक्षकारों की सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 27-6-1985 से अनावेदक का वादग्रस्त भूमि पर नामान्तरण हुआ। इस आदेश के विरुद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की जो प्रकरण क्रमांक 39/1984-85 पर दर्ज की जाकर आदेश दिनांक 31.12.1985 से निरस्त हुई। इस आदेश के विरुद्ध अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 95/1985-86 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.4.1990 से अपील अस्वीकार की। इसी आदेश से दुखी होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में उठाये गये बिन्दुओं पर हितबद्ध पक्षकारों के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालयों के अभिलेखों का अवलोकन किया गया।

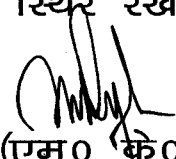


4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्कों पर विचार करने एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम अरदौनी स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 736 रकबा एक वीघा के सम्बन्ध में तहसील न्यायालय में मूल दावा यह लगाया गया है कि इस भूमि के पूर्व भूमिस्वामी दाताराम एवं गेंदालाल ने (तहसील न्यायालय में दावा प्रस्तुत वर्ष 83-84 के) 12-13 वर्ष पूर्व 5 रु. लगान लेकर जुतवा दिया था तब से इस भूमि पर निरन्तर काविज होकर खेती करते आ रहे हैं आवेदक का यह दावा नायब तहसीलदार मुरैना के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 21/83-84X110,190 में पारित आदेश दिनांक 26-9-84 से प्रमाणित होना पाया गया है, जिसे लगभग 31 का अंतराल हो चुका है। भले ही आवेदक क-2 यह तथ्य बता रहा है कि उसने वादग्रस्त भूमि आवेदक क-1 से कय की है किन्तु कय उपरांत उसे वादग्रस्त भूमि में वही अधिकार प्राप्त होंगे, जो विक्रय के समय विक्रेता को थे अर्थात् विक्रय दिनांक को वादग्रस्त भूमि सिकमी कास्त अधीन थी, जो नायब तहसीलदार मुरैना के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 21/83-84X110,190 में पारित आदेश दिनांक 26-9-84 से प्रमाणित है । आवेदकगण अनुविभागीय अधिकारी, मुरैना के समक्ष प्रकरण क्रमांक 39/1984-85 अपील में भी वादग्रस्त भूमि पर अपना स्वत्व व आधिपत्य सावित नहीं कर सके, जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी मुरैना ने आदेश दिनांक 31.12.1985 पारित करते समय अपील को सारहीन मानकर निरस्त करते हुये नायब तहसीलदार के आदेश दिनांक 27-6-85 को यथावत् रखा है। अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना ने प्रकरण क्रमांक 95/1985-86 अपील में पारित आदेश दिनांक 20.4.1990 में विवेचना कर निष्कर्ष निकाला है कि




अनुविभागीय अधिकारी मुरैना द्वारा आदेश दिनांक 31.12.85 में एवं नायव तहसीलदार मुरैना द्वारा आदेश दिनांक 27-6-85 में निकाले गये निष्कर्ष समरूप है जिसके कारण उन्होंने अपील में हस्तक्षेप नहीं किया है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है। परिणामतः अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण क्रमांक 95/85-86 अपील में पारित आदेश दिनांक 20 अप्रैल 1990 विधिवत् होने से स्थिर रखा जाता है।


(एम० के० सिंह)

सदस्य

राजस्व मण्डल, म०प्र०ग्वालियर


8/5